

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग

आदेश

गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक 12/12/2025—VVP-II Part-(I) दिनांक 31.10.2025 के आलोक में Vibrant Villages Programme-II (VVP-II) योजना को सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति निम्नरूपेण गठित किया जाता है :—

**1. राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (State Level Screening Committee - SLSC)**

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	संयोजक
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वारथ्य विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
14	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
15	सीमा सुरक्षा बल के राज्य स्तर से प्रतिनिधि	सदस्य
16	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	सदस्य
17	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावेद्यिकी विभाग	सदस्य
18	अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
19	अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग	सदस्य
20	अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य
21	अभियंता प्रमुख, लोक स्वारथ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्य
22	अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग	सदस्य

23	मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड	सदस्य
24	उपमहानिदेशक, प्रसार भारती	सदस्य
25	महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सदस्य
26	क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त Village Action Plan (VAP) में प्रस्तावित कार्यों/परियोजनाओं से संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार SLSC में शामिल किया जायेगा।

- (i) VVP-II के कार्यान्वयन के लिए योजना एवं विकास विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाता है।
- (ii) योजना एवं विकास विभाग के विभागीय प्रधान यथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को नोडल पदाधिकारी एवं प्रशाखा-10 के सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग को VVP-II के लिए सहायक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

#### **SLSC की Terms of Reference (ToR) निम्न प्रकार है :-**

- (i) योजना प्रक्रिया में जिला प्रशासन का अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन/सहयोग करना।
- (ii) राज्य में केन्द्रीय प्रक्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित/राज्य योजना अंतर्गत संचालित कराने वाले राज्य के नोडल विभाग का जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कराना एवं इन योजनाओं की मार्गदर्शिका/दिशा निदेश VVP-II की योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु उपलब्ध कराना।
- (iii) दिशा-निर्देश के अनुसार Village Action Plan (VAP) या कलस्टर स्तर की योजनाओं की जाँच करना।
- (iv) VVP-II के विशिष्टिताओं के अनुरूप चयनित गाँवों के मूल्य शृंखला विकास (किसान उत्पादक संगठनों/स्वयं सहायता समूहों के लिए सीड मनी, कार्यशील पूँजी) सीमा-विशिष्ट आउटरीच परियोजनाओं, पर्यटन सर्किट का विकास, स्मार्ट क्लासेज, आधारभूत संरचना विशेषकर आंतरिक सड़कें, आजीविका सृजन अथवा अन्य जनहित से संबंधित ग्राम-समूहों के लिए योजनाओं को तैयार करना।
- (v) Project Approval & Monitoring Committee (PA&MC) से अनुमोदन हेतु VAP या कलस्टर स्तर की योजनाओं की अनुशंसा करना।
- (vi) अनुमोदित कार्यों/परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय अनुश्रवण करना।
- (vii) अनुमोदित परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति में नीतिगत एवं अन्य बाधाओं का संज्ञान लेना।
- (viii) जिला स्तरीय टीम द्वारा योजनाओं की प्रगति का ससमय अद्यतनीकरण (Updation) सुनिश्चित करना।
- (ix) चिन्हित गाँवों में मौजूदा/नवसृजित बुनियादी ढाँचों का अधिकतम उपयोग के लिए मानव संसाधनों (डाक्टर/पारा-मेडिकल/शिक्षक/आशा/आँगनवाड़ी सेविका आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- (x) प्रस्तावित परियोजनाओं के तकनीकी व्यवहार्यता (Technical feasibility) एवं लागत की उपयुक्तता को प्रमाणित करेगा।
- (xi) SLSC की बैठक कम से कम 3 महीने में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार कम अंतराल में भी किया जा सकता है।

2. जिला स्तरीय समिति (District Level Committee - DLC)

1	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप विकास आयुक्त	सदस्य
3	जिला योजना पदाधिकारी—सह—सहायक नोडल पदाधिकारी	संयोजक
4	जिला पंचायतीराज पदाधिकारी	सदस्य
5	असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
6	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
7	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS)	सदस्य
8	महाप्रबंधक, उद्योग	सदस्य
9	कार्यपालक अभियंता, विद्युत	सदस्य
10	पर्यटन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	सदस्य
11	श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन	सदस्य
12	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य
13	जिला पशुपालन पदाधिकारी	सदस्य
14	जिला गव्य विकास पदाधिकारी	सदस्य
15	जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य
16	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
17	समादेष्टा, सीमा सुरक्षा बल	सदस्य
18	जिला जनसंपर्क पदाधिकारी	सदस्य
19	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण	सदस्य
20	कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन	सदस्य
21	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य	सदस्य
22	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	सदस्य
23	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण	सदस्य
24	प्रोजेक्ट प्रबंधक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सदस्य
25	भारत संचार निगम लिमिटेड के जिला स्तरीय प्रतिनिधि	सदस्य
26	परियोजना निदेशक, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य

जिला प्रशासन के कार्य :-

- VVP-II के लिए जिला पदाधिकारी संबंधित जिला के नोडल पदाधिकारी होंगे एवं जिला पदाधिकारी द्वारा सहायक नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा। सहायक नोडल पदाधिकारी संबंधित जिला स्तरीय समिति के संयोजक होंगे।
- Digital VVP पर गाँवों के Mapping के लिए राजस्व अभिलेखों के अनुसार जिला प्रशासन गाँवों का LGD Code का सत्यापन करेगा।

- (iii) जनांकिकी विवरणी (Demography Details), सामाजिक और आर्थिक संरचना, पूर्व से क्रियान्वित कार्यक्रमों का विवरण, संभावित पर्यटक रथल, पर्यटकों की संख्या आदि (मार्गदर्शिका की परिशिष्ट-III) (संदर्भित अध्याय-V) सहित गाँवों की रूपरेखा का जिला नोडल पदाधिकारी दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करेंगे।
- (iv) जिला नोडल पदाधिकारी चयनित गाँवों में क्रियान्वित भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों की विवरणी अद्यतन करेंगे तथा उन स्कीमों की पूर्णता के लिए कमी को चिन्हित करते हुए इसके लिए योजना तैयार करेंगे।
- (v) जिला नोडल पदाधिकारी कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण तथा कमियों का विश्लेषण कर Village Action Plan (VAP) तैयार करेंगे (संदर्भित अध्याय-V)।
- (vi) स्थानीय संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच क्रियाकलाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, त्योहार आदि का प्लान तैयार करने, इसके आयोजन इत्यादि की जिम्मेवारी जिला नोडल पदाधिकारी की होगी।
- (vii) कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण के अतिरिक्त, VVP-II अंतर्गत संचालित योजनाओं का Digital Platform पर पट्ट चार्ट (Work Flow) के अनुसार कार्य पूर्ण कराते हुए ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने तथा परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र समर्पित करने का दायित्व जिला नोडल पदाधिकारी का होगा। संपूर्ण कार्य प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी।
- (viii) जिला नोडल पदाधिकारी स्थानीय संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, इवेन्ट्स, मेला, त्योहार आदि के आयोजन का प्रयास करायेंगे।

#### **District Level Committee (DLC) की Terms of Reference (ToR) निम्न प्रकार है :-**

- (i) प्रस्तावित कार्यों/परियोजनाओं के लिए DPR के साथ Village Action Plan (VAP) तैयार कर अनुशंसा कराना।
- (ii) सभी प्रस्तावित कार्यों/परियोजनाओं के संबंध में सुनिश्चित करेगा कि –
  - (a) यदि प्रस्तावित स्कीम किसी मौजूदा/चालू स्कीम के अंतर्गत (Convergence) है तो उस स्कीम के मापदण्डों का अनुपालन हो रहा है।
  - (b) मौजूदा स्कीमों में समायोजन नहीं होने की स्थिति में VVP अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का अभ्युक्ति एवं औचित्य के साथ अनुशंसा किया गया है।
- (iii) प्रस्तावित परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता (Technical Viability), लागत की उपयुक्तता/औचित्य (प्रस्ताव गठित करने में प्रयुक्त नियम/शर्तों की सुरक्षितता के साथ) को प्रमाणित करेगा।
- (iv) सभी प्रस्तावित परियोजनाओं का Geo-tagged Location सुनिश्चित करना।
- (v) परियोजनाओं का ससमय पूर्ण कराये जाने हेतु अनुश्रवण करना।
- (vi) क्लस्टर परियोजनाओं को State Level Committee (SLC) को प्रस्तावित करना।
- (vii) District Level Committee (DLC) की बैठक महीने में एक बार होगी।

(viii) कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाएं ससमय पूर्ण हो, इसके लिए जिला स्तरीय समिति बैठक में इसका अनुश्रवण करेगा। जिला स्तरीय समिति सभी परियोजनाओं का रख-रखाव सुनिश्चित करेगा तथा इस कार्यक्रम के तहत सृजित परिसम्पत्तियों एवं आधारभूत संरचनाओं पर उपयोग शुल्क (User Charges) का अधिरोपन की अनुशंसा/अनुमोदन करेगा।

उपर्युक्त के संदर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र/दिशा-निर्देश की छायाप्रति संलग्न है।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

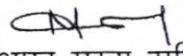
 19.1.26  
(डॉ एन० विजयलक्ष्मी)

अपर मुख्य सचिव

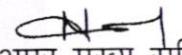
ज्ञापांक: यो010 / VVP-II-02 / 2025 - 282 / यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं प्रावैद्यिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010 / VVP-II-02 / 2025 - 282 / यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, पटना / महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, बिहार, पटना / उप महानिदेशक, प्रसार भारती, पटना / महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना / क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010 / VVP-II-02 / 2025 - 282 / यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण / पश्चिमी चम्पारण / सीतामढ़ी / मधुबनी / सुपौल / अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010 / VVP-II-02 / 2025 - 282 / यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010/VVP-II-02/2025 - 282/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: निदेशक, सीमा प्रबंधन प्रभाग-II, गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन विभाग), भारत सरकार,  
नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010/VVP-II-02/2025 - 282/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य  
विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010/VVP-II-02/2025 - 282/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/सीतामढ़ी/मधुबनी/सुपौल/  
अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010/VVP-II-02/2025 - 282/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई  
हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010/VVP-II-02/2025 - 282/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: जिला योजना पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी  
चम्पारण/सीतामढ़ी/मधुबनी/सुपौल/अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010/VVP-II-02/2025 - 282/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: संबंधित जिला के जिला पंचायतीराज पदाधिकारी/असैनिक शत्य  
चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला  
कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS)/ महाप्रबंधक, उद्योग/पर्यटन विभाग के जिला स्तरीय  
पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला  
पशुपालन पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी/जिला मत्स्य  
पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/समादेष्टा, सीमा सुरक्षा बल/ जिला जनसंपर्क  
पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010/VVP-II-02/2025 ~ 282 /यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण/जल संसाधन/ग्रामीण कार्य/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/भवन निर्माण/विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010/VVP-II-02/2025 ~ 282 /यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: संबंधित जिला के प्रोजेक्ट प्रबंधक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/भारत संचार निगम लिमिटेड के जिला स्तरीय प्रतिनिधि/परियोजना निदेशक, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010/VVP-II-02/2025 ~ 282 /यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: यो010/VVP-II-02/2025 ~ 282 /यो0वि0, पटना, दिनांक 19 जनवरी, 2026  
प्रतिलिपि: श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 19.1.26  
अपर मुख्य सचिव

No. 12/12/2025-VVP-II Part(1)

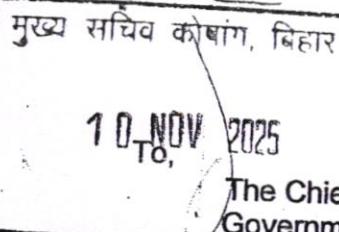
भारत शासन / Government of India

गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs

सीमा प्रबंधन विभाग / Department of Border Management

सीमा प्रबंधन-II प्रभाग / Border Management - II Division

Acc, Home



The Chief Secretary,

Government of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, J&K, Ladakh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal.

Major Dhyan Chand National Stadium,  
New Delhi-110001,  
Dated the 31<sup>st</sup> October, 2025

11 NOV

Sir,

I am directed to refer to the subject mentioned above and to say that a workshop on Vibrant Villages Programme was held on 25<sup>th</sup> and 26<sup>th</sup> August during which the implementation guidelines of VVP-II was issued.

2. At the State/UT level the State Government/UT Administration shall constitute a State Level Screening Committee (SLSC)/ UT level Screening and Committee under the chairmanship of Chief Secretary for screening projects and for review of the programme. The composition and Terms of Reference (ToR) for SLSC/UTLSC is attached at Annexure.

3. At the District level there shall be a District Level Committee (DLC) headed by District Magistrate/Deputy Commissioner with representation of concerned line agencies for planning & implementation of VVP-II. The DLC would also co-opt representative nominated by concerned BGFs to incorporate the strategic needs of developmental projects in respect of identified villages. The Terms of Reference (ToR) for DLC is attached at Annexure.

4. Therefore, it is requested to constitute SLSC/UTLSC & DLC at the earliest.

5. This issues with the approval of competent authority.

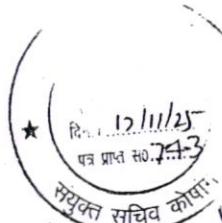
Encl: As above

Yours Faithfully,

Manish Srivastava  
Director  
Tel: 23075292

प्रधान प्राप्ति शाखा  
गृह विभाग (विशेष शाखा)  
कला विभाग  
प्रभाग सं. 120  
प्रभाग सं. 120

2967/सू. 120  
12.11.25  
VS(F)



a.	Union Cabinet Secretary	Chairman
b..	Union Home Secretary	Member
c.	Secretary (Border Management)	Member
d.	Secretary (Expenditure)	Member
e.	Secretary (of concerned ministry/department whose scheme guidelines needs relaxation	Member

4.1.7 The HPC will have authority to undertake relaxations in schematic guidelines of Central Sector and Centrally Sponsored schemes of various ministries, including PMGSY-IV, for effective implementation in these border villages. The Terms of Reference (ToR) of the HPC are at **Annexure II**.

## 4.2 STATE GOVERNMENT/UT ADMINISTRATION

4.2.1. State Government/UT Administration shall ensure availability of land for the proposed projects. Any costs involved for acquisition of such lands, including Forest Clearance, or any other incidental costs shall be borne by the State Government/UT Administration.

4.2.2 State Government/UT Administration shall ensure that operating costs, maintenance and necessary & appropriate manpower shall be made available for the proposed projects.

4.2.3 State Government/UT Administration would constitute State Level Screening Committee (SLSC)/UT Level Screening Committee (UTLSC) with the following composition:

a.	Chief Secretary/Advisor	Chairman
b..	Representative of Road Construction Agency/CPWD/PWD	Member

c.	Representative of Department of Health	Member
d.	Representative of Department of Education	Member
e.	Representative of Department of Women & Child Welfare	Member
f.	Representative of Department of Industry	Member
g.	Representative of Department of Power	Member
h.	Representative of Department of Tourism	Member
i.	Representative of Department of Skill Development	Member
j.	Representative of Department of Cooperation	Member
k.	Representative of Department of Animal Husbandry/fishing	Member
m.	Representative of Department of Agriculture	Member
n.	Representative of Department of Rural Development	Member

4.2.4 Beside above, the SLSC/UTLSC will bring on board representative of a department concerned with the works/projects proposed in VAP, as & when required.

4.2.5 SLSC/UTLSC would also co-opt representatives from concerned BGFs to ensure that the strategic objectives of VVP-II are ensured.

4.2.6 SLSC/UTLSC shall meet at least once in 3 months or in lesser interval, as needed.

4.2.7 **Terms of Reference (ToR) for SLSC/UTLSC:** ToR of SLSC/UTLSC are as follows:

- i. Nominating a Nodal department within the existing administrative arrangement for implementation of VVP-II.
- ii. Nominating the Head of the nominated department as Nodal Officer and an Assistant Nodal Officer for VVP - II.
- iii. Monitoring & Handholding of District Administration in the planning process.
- iv. Ensuring coordination of district administration with nodal departments implementing CS/CSS/State/UT Schemes hand and availability of operational/schematic guidelines of these schemes to the district administration for robust planning.
- v. Examination of comprehensive Village Action Plan (VAP) or cluster level plans as per these implementation guidelines.
- vi. Preparation of plan(s) for a cluster of villages for value chain development (seed money, working capital for FPOs/SHGs) of select villages, border specific outreach projects, development of tourist circuits, SMART classes, infrastructure gap filling especially internal roads, livelihood creation or any other public purpose in line with objective of VVP – II.
- vii. Recommendation of VAP or cluster level plans for approval by PA&MC.
- viii. Physical & financial monitoring of the approved works/projects.
- ix. To take note of policy and other bottlenecks in physical & financial progress of approved projects.
- x. Ensure real time updation of the progress by the district teams.
- xi. Ensure availability of human resources (doctors/para-medics/teachers/ASHA/Anganwadi Sevika etc.) for optimum utilization of existing/created infrastructure in identified villages.
- xii. Shall certify technical feasibility and cost appropriateness of the projects proposed.

### 4.3 DISTRICT ADMINISTRATION

4.3.1 The DM/DC shall be the Nodal Officer (DNO) and shall appoint an Additional Nodal Officer (ANO) for the programme. The Additional Nodal Officer shall be the convenor of the DLC.

4.3.2 District administration would verify the village LGD code as per revenue records for mapping of villages on the Digital VVP. This will be helpful in mapping of data available with other Ministries/Departments and organisations for a complete analysis of saturation of schemes in the villages during a fixed time-frame.

4.3.3 The DNO shall ensure documentation of the village profile including demographic details, social and economic infrastructure, details of on-going programmes, potential tourists sites, footfall, etc. (**Annexure III**) (Refer chapter V.).

4.3.4 The District NO shall update the details under various schemes of the Government of India under implementation in the village and identify gaps and prepare a plan for its saturation.

4.3.5 The District NO shall carry out baseline survey and gap analysis for the preparation of VAP to meet the specific objectives of the programme. (Details of gap analysis in Chapter- V).

4.3.6 It shall be the responsibility of the District NO to plan, organise and undertake outreach activities, cultural programme, fairs, festivals, etc. to promote the local culture and heritage.

4.3.7 Apart from regular monitoring of the programme, the District NO shall be responsible for ensuring timely submission of UCs and Project Completion Certificate. The entire workflow shall be on a digital platform.

4.3.8 The District NO shall take efforts to organize cultural programmes, events, fairs, festivals to promote local culture and heritage.

#### **4.4 DISTRICT LEVEL COMMITTEE (DLC)**

4.4.1 At the district level there would be a DLC headed by District Magistrate/Deputy Commissioner with representation of concerned line agencies viz. Road construction agency, Women & Child development, Panchayati Raj, Rural Development, Skill Development, power, tourism etc. for planning & implementation of VVP-II.

4.4.2 The DLC will also co-opt representative nominated by concerned BGFs to incorporate the strategic needs of developmental projects in respect of identified villages.

##### **4.4.3 TERMS OF REFERENCE (TOR) FOR DLC**

- i. Responsible for preparation and recommendation of VAP with the DPRs for the works/projects.
- ii. Shall ensure all proposed works/projects –
- iii. Comply with scheme norms if proposed under any existing Scheme (Convergence)
- iv. Recommended with remarks, reason for proposing works under VVP in spite of fitting into an existing Scheme.
- v. Shall certify the technical viability, reasonability of cost (with clarity on norms/rules used to make such proposals) and economic/social viability of a proposed projects.
- vi. Ensure geo-tagged location of all proposed projects.
- vii. Monitor the timely completion of the projects.
- viii. Propose cluster projects and works to the SL/UT Committee.
- ix. The DLC shall meet once a month.

4.4.4 The DLC shall in its meeting monitor the timely completion of projects. It shall ensure maintenance of all projects and recommend/approve levy of user-charges on the assets and infrastructure created under the programme.



**वाइब्रेंट विलेजेज, सशक्त सीमाएं**  
**VIBRANT VILLAGES, EMPOWERED BORDERS**

**VIBRANT VILLAGES PROGRAMME-II**  
**(2024-25 to 2028-29)**

**[CENTRAL SECTOR SCHEME]**

---

**IMPLEMENTATION GUIDELINES**

**Ministry of Home Affairs**  
**Government of India**  
**New Delhi**

## CHAPTER - V

### PLANNING PROCESS

#### **5.1 PREPARATION OF VILLAGE PROFILE AND BASELINE SURVEY**

5.1.1 For an effective planning exercise, the profile of every village must be prepared. The district administration shall take necessary steps to ensure that the information on the profile is reliable and accurate. The exercise must be completed in 3 months after the launch and conduct of state level workshop on the programme. The data shall be mandatorily uploaded on the digital VVP portal. The profile template is annexed.

5.1.2 The profile shall include the demographic details, geographic information, existing socio-economic infrastructure details, cultural traits of the village, livelihood sources, economic opportunities like tourism possibilities, etc.

5.1.3 The district shall update the status of implementation of various schemes under GoI under implementation in the identified village. It shall identify and list the gaps for coverage of individual/HH level benefit schemes.

#### **5.2 GAP ASSESSMENT**

5.2.1 Based on the Village Profile, the district administration shall carry out **baseline survey for existing projects and schemes** in the identified village in order to identify gaps in existing basic physical and social infrastructure and coverage under individual/household/community benefit schemes. Existing data bases from vetted sources of Government of India and the State/UT Government may be used for the said purpose.

5.2.2 As an illustration, the district will compile the demographic details and data recorded under various government registries such as health / PDS / Immunization cards etc which will be helpful in ascertaining the present socio-economic indicators and later assessing the outcome of the programme. District will ensure uploading the data on the digital portal.

5.2.3 The gap identification exercise should involve all relevant stakeholders including the reps from BGFs. A suggestive list is as follows:

- o Socio-economic infrastructure like health centers
- o Basic infrastructure like roads and telecom
- o Enabling infrastructure like banks, post offices

### **5.3 – PREPARATION OF THE VILLAGE ACTION PLAN (VAP)**

5.3.1 Village Action Plan (VAP) is a comprehensive, collectively prepared plan that outlines the developmental needs, priorities, and actionable steps for transforming a remote border village into a self-sustaining, vibrant community.

5.3.2 The plan shall be prepared by the district administration in a collaborative and participatory approach along with the BGFs, community, domain departments in the State and Departments of Government of India. A tentative format is illustrated below. The exercise shall be undertaken on the digital VVP portal.

## ACTION PLAN MATRIX (ILLUSTRATIVE)

Sector	Project	Term	Tentative Timeline	Implementing Agency (Dept in State)	Scheme/Ministry (GoI)	Ownership and maintenance (OPEX)	Expected Outcome
Education	Renovate primary school	Medium	1 year	State Education Department	SSA	SSA	Improved learning environment
Connectivity	Build approach road to village	Medium	2 years	State PWD	PMGSY	State PWD	Better access to services
Livelihood	Skill training for youth (tourism)	Long	3 months	District Skill Centre	VVP	Tourism dept of the State	Local employment generation

5.3.4 During the preparation of the plan, the sustainability of the project should be considered. For example, in a livelihood project, the supply chain, the possibility of value-addition and its market should be explored, analyzed and considered. Similarly, in infrastructure projects, maintenance and operating cost should be clearly indicated and figured in. The availability of encumbrance free land should be clearly indicated.

5.3.5 The OPEX, maintenance and operating cost shall be the responsibility of the State/UT Government. In case land acquisition would be required, the same shall be undertaken by the State/UT Government with their own cost and the State/UT administration shall ensure such land is made available.

5.3.6 The District Collector being the **Nodal Officer** for the programme, is expected to have a comprehensive approach of the plans and hence, a consolidated statement by the

District Collector shall be filled and uploaded (Annex). This statement shall elaborate on the short-term, medium-term and long-term development priorities and objectives for the border blocks. For example, repairing roads, installing solar lights would be short-term, while setting up a health sub-center, training youth in digital literacy would be medium term and Eco- tourism development, establishing agro-processing units would be long-term.

5.3.7 The VAP shall be uploaded on the portal and visible to all the nodal departments of the State/UT. Once cleared by the departments, the same shall be placed before the State Level Screening Committee chaired by the Chief Secretary for his concurrence. The VAP shall then be submitted to the Project Sanctioning and Monitoring Committee, MHA for sanction.

5.3.8 Once the plans are received, the works/proposals which fall in the purview of any existing scheme would be considered by the said Ministry under their existing scheme. If the same cannot be considered under then the same may be considered under the VVP programme.

5.3.9 A well-prepared **Village Action Plan** becomes the foundation for implementing VVP initiatives effectively, ensuring that development is tailored to the village's specific needs and is both sustainable and impactful.

#### 5.4 GUIDELINES FOR PREPARING THE VAP ARE AS FOLLOWS

- i. Formulation of proposals/detailed estimates/Detailed Project Report (DPR) shall aim to attain saturation in terms of infrastructure or coverage of schemes
- ii. Effort to be taken to submit a comprehensive action plan duly considering the gaps rather than sending proposals in intervals. Care should be taken to ensure that the proposals should attempt to meet the objective of the programme.
- iii. Projects/works should be proposed as per scheme norms if the works/project falls broadly within existing schemes of Central Ministries/Departments.
- iv. If the works/projects broadly fit for coverage under existing schemes of Central Ministries/Departments then DLC would obtain necessary technical & cost inputs in coordination with the concerned Departments or regional offices of Central Govt. to ensure its consideration
- v. DLC for the purpose of identification of schemes, which may fall under convergence, may refer to the illustrative list of CS/CSS is given at **Annexure I**, and for reference purpose, the table illustrating the broad features of some of the schemes is given below:
- vi. If the works/projects broadly fit for coverage under existing schemes of Central Ministries/Departments and still DLC recommends for taking up it under VVP-II, a detailed justification indicating the reasons for its non-consideration by concerned departments at State level under the existing scheme(s).
- vii. While preparing the DPR, DLC would take care that funding under the VVP-II would not be meant for individuals. Formation of group of individuals like SHGs/FPOs would be a pre-requisite for taking advantage available for livelihood generation projects under VVP – II or other such schemes of Central Ministries/Departments as per their schematic norms
- viii. DLC would ensure about 100% availability of land and all requisite statutory clearances for the works/projects before finalizing the projects. This will ensure timely completion of the works/projects. No part of funds allocated is to be used for land acquisition under any circumstances.

- ix. DPR would ensure that the work implementation plan has invariably taken into consideration about the availability of requisite human resources, prevailing weather conditions and OPEX, including user charges, for maintenance of assets created under the programme.
- x. DLC would ensure that the proposed works/projects have been correctly photographed at pre-execution stage with geo-tagging of the site indicating the longitude/latitude at the time of identification of infra works/projects.
- xi. While planning the works/projects, DLC will ensure leverage of modern technologies like drones, GIS based decision making, BIM, 3D printing, precast / prefabricated construction technology, precision agriculture etc. to ensure quality and rapid project conceptualization.
- xii. Keeping above in consideration DLC will prepare the VAP and submit the same on online portal – Digital VVP through GeoSnap-APP. A template for the GeoSnap-App is at **Annexure V**.
- xiii. DLC will ensure that works/proposed under the programme should be checked and approved by competent Technical Authority. The “Abstract of cost” of each work / project duly signed by the appropriate Technical Authority must be uploaded on the Digital VVP while submitting the plan.
- xiv. Escalation in cost estimates would not be generally agreed by Project Approval & Monitoring Committee (PA&MC) except in very rare circumstances.
- xv. Religious works/projects will not be permitted under the programme.
- xvi. No repairs and maintenance works of either new works or existing works will be permitted under the programme.

\*\*\*\*\*

Annexure – III

**TEMPLATE OF VILLAGE PROFILE**

S. No.	Parameter Description	Data Type
1	<b>Cultural/Historical Significance</b>  1) Brief Cultural/ Historical Heritage of the Village, if any	Text
2	<b>Demographic Profile</b>  1) Total Population 2) Male population 3) Female population 4) ST Population 5) SC Population 6) Presence of seasonal migrant population 7) Number of Households (HH) 8) Male Literacy Rate (in %) 9) Female Literacy Rate (in %)	Nos. Nos. Nos. Nos. Nos. Yes/No Nos. Percentage (%) Percentage (%)

3	Village Infrastructure Profile	
	A. Road connectivity	
	1) Whether connected by all-weather road	Yes/No
	B. Telecom connectivity	
	1) Telecom connectivity- 4G and above	Yes/No
	i. If no, then	
	a) Site selection/identification	Yes/No
	b) Land acquisition for tower	Yes/No
	c) Tower foundation completed	Yes/No
	d) Tower operationalized	Yes/No
2) Telecom connectivity- 2G/3G		Yes/No
C. Electrification		
1) Availability of On-Grid electricity		Yes/No
a) If yes, no. of households having electricity through On-Grid		Nos
3) Availability of Off-Grid electricity		Yes/No
a) If yes, no. of households having electricity through Off-Grid		Nos

4) % of households electrified through On-grid electrification	Auto calculated <sup>1</sup>
<b>D. Piped Water Supply</b>	
1) Whether village JJM compliant	Yes/No
2) Number of HHs having piped water supply	Nos
3) Number of HHs not having piped water supply	Auto calculated <sup>2</sup>
<b>E. Sanitation</b>	
1) No. of HHs having toilets/IHSL	Nos
2) % of HHs having IHSL	Auto calculated <sup>3</sup>
<b>F. Health</b>	
1) Whether Healthcare Infrastructure is available	Yes/No
2) If yes, what type of healthcare infrastructure is available (PHC/CHC/Sub-Centre/Other)	Text
3) Number of Asha workers in the village	Nos.
4) Distance of the village from nearest available health facility (in Kms.)	Nos.
5) Availability of transportation in case of referral	Yes/No

<sup>1</sup> % of households electrified through On-grid electrification =  $\frac{3 C (2)}{2 (7)}$

<sup>2</sup> Number of HHs not having piped water supply = 2 (7) - 3 D (2)

<sup>3</sup> % of HHs having IHSL =  $\frac{3 E (1)}{2 (7)}$

	<b>G. Education</b>	
1)	Whether educational infra-available in the village	Yes/No
a)	Primary School/ Middle School	Yes/No
b)	High School/ Higher Secondary School	Yes/No
2)	Number of Anganwadi/Balwadi/Model Anganwadi Centres	Nos.
	<b>H. Village Internal Infra</b>	
1)	Availability of Multi-purpose community hall	Yes/No
2)	Availability of Public Distribution System (PDS)	Yes/No
3)	Availability of Common Service Centre (CSC)	Yes/No
	<b>I. Market</b>	
1)	Market facility available within village (Market/mandi/Bazaar/Haat/Others)	Yes/No
	<b>J. Land Use Pattern</b>	
1)	Land use in hectare (ha)	Nos.
2)	Source of irrigation (canal/ground water/rainfed/other)	Text
3)	Availability of vacant Govt. land (ha)	Yes/No
4	<b>Enabling Infrastructure in Village</b>	
	<b>A. Financial Inclusion</b>	

1) Is Bank branch available in the village	Yes/No
2) Is post office available in the village	Nos.
a) If yes, whether IPPB available	Yes/No
3) Is Bank Mitra/Bank Sakhi is available in the village	Yes/No
4) If Bank branch not available, distance from the nearest Bank branch (in kms)	Nos
5) Availability of ATM facility	Yes/No
<b>B. Cooperatives, FPOs and SHGs</b>	

1) Is Cooperative available	Yes/No
2) Is SHG available	Yes/No
3) Is FPO available	Yes/No
<b>C. Television connectivity</b>	
1) No. of HHs having television connectivity	Nos
2) Percentage (%) of households having television	<b>Auto calculated<sup>4</sup></b>
<b>5 Livelihood Profile</b>	
1) Major Occupation/livelihood in the village	Text
<b>6 Tourism Profile</b>	

1) Unique Geographical features	Text
2) Tourist spots/places of historical/cultural/religious significance	Text
3) Tourist footfall (per annum)	Nos.
4) Availability of homestay, tourist centre, hotel, guesthouse etc	Yes/No
5) Tourist season (duration in months)	Nos.

<sup>4</sup> Percentage (%) of households having television =  $\frac{4C(1)}{2(7)}$